सत्यमेव जयते

पंजाब के राज्यपाल

श्री बनवारीलाल पुरोहित

द्वारा

विधान सभा

में

दिनांक 21 मार्च, 2022 दिन सोमवार

को दिया गया

भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आदरणीय सदस्यगण,

मैं 16वीं पंजाब विधानसभा के उद्घाटन सत्र में आप सभी का गर्मजोशी से हार्दिक स्वागत करता हूं और आम चुनाव में आपकी सफलता के लिए आप सभी को बधाई देता हूं।

2. सर्वप्रथम, मैं पंजाब के लोगों को राज्य में हाल ही में संपन्न विधान सभा चुनावों में उनके द्वारा प्रदर्शित दृष्टिकोण की उल्लेखनीय स्पष्टता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह बड़े संतोष की बात है कि चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई। इसका सारा श्रेय पंजाब के लोगों, राज्य प्रशासन के अधिकारियों और भारत के चुनाव आयोग को जाता है।

3. पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए बड़ी संख्या में मतदान किया है और हमारी सरकार को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। उनका यह जनादेश उम्मीदों और आकांक्षाओं के बारे में है। उन्होंने न केवल शासन के लिए एक नए दृष्टिकोण में बल्कि एक नई राजनीतिक संस्कृति में भी विश्वास व्यक्त किया है जो हमारे विचारों, कार्यों और नीतियों को नागरिकों पर केंद्रित रखने की आवश्यकता पर बल देता है। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि राज्य के लोगों ने राज्य और देश में लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय रचा है।

4. हमारी सरकार बड़ी विनम्रता और गहरी आशा के साथ पंजाब के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश को स्वीकार करती है। यह एक ऐसा जनादेश है जो जाति, वर्ग या धर्म से ऊपर उठ कर आम आदमी के सपनों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। लोगों ने एक सामूहिक व जबर्दस्त संदेश दिया है। वे स्वच्छ राजनीति से उभरने वाला सुशासन चाहते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए

उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ने के लिए अपनी उत्सुकता दिखाई है। निराशावाद के दौर में पंजाब के लोग अच्छे दिनों की आशा में खुशहाल पंजाब की उम्मीद में इन्कलाब लाने के लिए एकजुट हुए हैं।

5. हमारी सरकार का मानना है कि पंजाब को एक शब्द में परिभाषित किया जा सकता है – क्षमता। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि पंजाब के प्रत्येक नागरिक को अपने सपनों और क्षमता को साकार करने का अवसर मिले। और इस क्षमता को साकार करने के लिए, हमें भविष्य की ओर देखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है।

हमें ऐसे पंजाब की ओर बढ़ना है, जहां सबका सम्मान हो।

हमें ऐसे पंजाब की ओर बढ़ना है, जहां सबके लिए रोजगार हो।

हमें ऐसे पंजाब की ओर बढ़ना है, जहां प्रगती में लोगों की भागीदारी हो।

हमें ऐसे पंजाब की ओर बढ़ना है, जहां हमारी महिलाएं सुरक्षित और स्वस्थ हों।

हमें ऐसे पंजाब की ओर बढ़ना है, जहां हमारे किसान समृद्ध और सम्मानित हों।

एक ऐसा पंजाब जो मिसाल कायम कर अग्रणीय हो और देश का नंबर 1 राज्य बने।

एक ऐसा पंजाब, जहां हमारे भविष्य की नींव में पंजाबीयत हो।

एक ऐसा पंजाब जो निडर और गौरवशाली हो।

हमें ऐसे पंजाब की ओर बढ़ना है, जो अपने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे।

एक ऐसा पंजाब, जो शहीद भगत सिंह और बाबा अंबेडकर के सपनों को साकार करता हो।

मेरे पंजाब वासियो, आपके प्रति हमारी सरकार की यही प्रतिबद्धता है कि हमारी सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेगी।

क्योंकि पंजाब की जान इसके निवासी हैं।

हमारी सरकार का मानना है कि लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है (जनता राज में जनता ही राजा)। और हमारी सरकार इस सिद्धांत का पालन करेगी।

6. हमारी सरकार का इरादा लोगों को उन मुद्दों में शामिल करके अपने लोकतंत्र को गहरा और मजबूत बनाना है जो उन्हें दैनिक आधार पर प्रभावित करते हैं। हमारी सरकार का मानना है कि सुशासन को समाज के सभी वर्गों की चिंताओं को उजागर करना चाहिए। समान रूप से, विकास में प्रत्येक नागरिक की भलाई शामिल होनी चाहिए। एक सुरक्षित और प्रगतिशील पंजाब का लक्ष्य तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रत्येक नागरिक अपनी आजीविका, अपनी जीवन शैली और विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षित महसूस न करे। हमारी सरकार का प्रयास होगा कि पंजाब के लोगों से किए गए सभी वायदों को पूरा किया जाए और जनता ने हमारी सरकार में जो विश्वास जताया गया है, उस पर खरा उतरा जाए।

7. पिछले पांच वर्षों में लोगों और सरकार के बीच एक गंभीर अलगाव देखा गया है। शासक न केवल आम लोगों के लिए अपितु अपने प्रतिनिधियों की पहुंच से

भी बाहर हो गए थे। वे स्वयं को स्वामी और लोगों को अपनी दारा प्रजा के रूप में देखने लगे थे। यह लोकतंत्र की उस अवधारणा के विरुद्ध था, जिसमें स्वामी केवल लोग ही होते हैं और सरकार में बैठे लोगों को एक कर्तव्यनिष्ठ सेवक के रूप में कार्य करना होता है। हमारी सरकार के लिए सुगम्यता वह आधारशिला है जिस पर जनता के साथ उसके भरोसे और आपसी स्नेह के रिश्ते की नींव टिकी हुई है। हमारी सरकार न केवल हर पंजाबी का उनके दरवाजे पर स्वागत करना चाहती है, बल्कि राज्य के कोने–कोने में उन तक, खासकर गरीबों तक, पहुंचना चाहती है।

8. हमारी सरकार के लिए चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र राज्य के मामलों में व्यक्तिगत और राजनीतिक कटुता का व्याप्त होना है। चरित्र हनन, जो कभी भी पंजाबी संस्कृति का अंग नहीं रहा, आदर्श बन गया था। यह प्रवृत्ति पिछले वर्षों के दौरान पंजाब में देखी गई टकराववादी राजनीति की बुनियाद में भी थी। इस के प्रभाव पंजाब और उसके लोगों के भविष्य के लिए केवल विनाशकारी हो सकते हैं, क्योंकि इसने उस रचनात्मक ऊर्जा को नष्ट कर दिया जो सत्ताधारी और विपक्षी दलों द्वारा मिल कर किए गए रचनात्मक कार्य से प्रवाहित हो सकती थी। राज्य के लोगों ने व्यापक पंजाबी आम सहमति के आधार पर सुशासन और विकास के पक्ष में मतदान करके इस टकराववादी प्रवृत्ति को सिरे से खारिज कर दिया है। हमारी सरकार वास्तव में इस जनादेश का सम्मान करती है और इसके मार्गदर्शन में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध है और कानून ही किसी भी पथभ्रष्टता से निपटेगा। इस के लिए सार्वजनिक हस्तियों के आचरण में मर्यादा और गरिमा के कुछ न्यूनतम मानकों पर सर्वदलीय सहमति की आवश्यकता होगी।

9. राज्य के लोगों ने समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ बार–बार अपनी बुलंद आवाज को व्यक्त किया है। हाल ही में संपन्न हुए चुनावों का फैसला भी इस खतरे के खिलाफ जनादेश था। समस्या के लक्षण सामने हैं, जिसके वास्तविक कारण हमारे समाज में नैतिक मानकों में सामान्य, चौतरफा और व्यापक पतन में पसरे हुए हैं। इस को ठीक करने हेतु सरकार और विपक्षी दल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। पंजाब की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग का नेतृत्व करेगी।

10. हमारी सरकार की नीति में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार, अपनी ओर से शासन के प्रति अपने दृष्टिकोण में एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को मुख्य सिद्धांत बनाएगी। हमारी सरकार प्रदेश में हर तरह के परिवहन, शराब, रेत माफिया आदि को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन असामाजिक तत्वों ने पिछली सरकारों के दौरान पंजाब को लूटा है और राज्य के खजाने को हजारों करोड़ रुपये का चूना लगाया है जिसका इस्तेमाल आम लोगों के कल्याण के लिए किया जा सकता था।

11. स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी मानव और सामाजिक विकास का आधार हैं। हमारी सरकार इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समग्र सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। तदानुसार, शैक्षिक और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत और इस का प्रसार करने के लिए नीतियां विकसित और कार्यान्वित की जाएंगी।

12. मौजूदा अस्पतालों को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा और बड़े पैमाने पर नए अस्पताल विकसित किए जाएंगे। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक को विश्व स्तरीय और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।

प्रदेश के हर नागरिक का सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह से निःशुल्क होगा, जैसा कि निजी अस्पताल मुहैया कराते हैं। दवाएं अस्पताल में ही मुहैया करवाई जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अस्पतालों में मशीनें पूरी क्षमता से काम करें।

13. राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा, जिस पर सारी जानकारी पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसके अलावा, दिल्ली में 'मोहल्ला क्लीनिक' की तर्ज पर पूरे राज्य में 16000 पिंड और वार्ड क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे।

14. हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सड़क दुर्घटना से पीड़ित हर व्यक्ति को बचाया जा सके। इसके लिए दिल्ली में 'फरिश्ते' योजना की तर्ज पर राज्य में एक योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को ले जाकर किसी भी अस्पताल में भर्ती करा सकता है जहां उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अस्पताल कितना महंगा है या इलाज कितना महंगा है, व्यक्ति को मुफ्त इलाज दे कर उसकी जान बचाई जाएगी।

15. हमारी सरकार का मानना है कि राष्ट्र निर्माण के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी है। हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण परिवर्तन के लिए काम करेगी। दिल्ली की तर्ज पर हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा निजी स्कूलों से बेहतर हो। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आम जनता पर बोझ कम करने के लिए स्कूल फीस को विनियमित किया जाए।

16. हमारी सरकार पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल माहौल बनाने के लिए

प्रतिबद्ध है। पंजाब में अधिकांश शिक्षक पिछले 18 वर्षों से केवल 10,000 रुपये प्रति माह पर काम कर रहे हैं, जो कि नाइंसाफी थी। शिक्षकों को गैर–शैक्षणिक कार्य सौंपे जाते थे। शिक्षकों के पदों में भारी संख्या में रिक्तियां हैं और मौजूदा उपलब्ध शिक्षकों के लिए आधुनिक शिक्षण विधियों के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं है।

17. हमारी सरकार मौजूदा रिक्तियों के लिए स्थायी भर्ती करेगी और मौजूदा आउटसोर्स और अनुबंधित शिक्षक नौकरियों को नियमित करने के लिए नीति तैयार करेगी। शिक्षण की गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए, मैनेजमेंट संस्थानों के साथ–साथ शिक्षकों को भी देश के फिनलैंड, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में आधुनिक शिक्षण विधियों में प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाएगा। शिक्षकों को कोई गैर–शिक्षण कार्य नहीं सौंपा जाएगा ताकि वे छात्रों के शिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकें जिससे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता पर साकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

18. हमारी सरकार शिक्षकों की तकलीफों को कम करने के लिए एक पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाएगी। शिक्षकों की पदोन्नति की एक नीति बनेगी। शिक्षकों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

19. पंजाब में बिजली एक बहुत बड़ी समस्या है और स्थिति बहुत खराब है। बिजली सरप्लस राज्य होने के बावजूद, पंजाब में बिजली की दरें भारत में सबसे अधिक हैं क्योंकि निजी बिजली संयंत्रों और सत्ता में रहने वालों के बीच एक सांठगांठ बनी हुई थी। हमारी सरकार पंजाब की जनता और राजकोष को इस सांठगांठ से मुक्ति दिलवाने के लिए कटिबद्ध है।

20. भले ही पिछली सरकार ने देश के बाकी हिस्सों की तुलना में पंजाब में सस्ती बिजली का झूठा प्रचार किया था और सभी घरेलू बिलों के बकाया या भुगतान न किए गए बिलों को माफ करने का झूठा दावा किया था लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सरकार पंजाब में हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे लगभग 80% घरों में बिजली का बिल शून्य हो जाएगा। बिजली के बिल/बकाया का भुगतान न करने के कारण जो घरेलू बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे, उन्हें बहाल किया जाएगा।

21. हमारी सरकार पंजाब में चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे लागू करने में कुछ समय लगेगा। 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने में करीब दो से तीन साल का समय लगेगा। निःसंदेह किसानों के लिए मुफ्त बिजली और उद्योगों के लिए टैरिफ की वर्तमान दर सहित सभी मौजूदा बिजली योजनाएं जारी रहेंगी।

22. हमारी सरकार किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उनकी समस्याओं को कम किया जा सके। अन्नदाता स्वयं को असयाह महसूस न करे। हमारी सरकार कृषि को सम्मानजनक व्यवसाय बनाकर इसे लाभदायक बनाएगी। इस वर्ष के दौरान प्राकृतिक कारणों से प्रभावित किसानों को न केवल मुआवजा दिया जाएगा बल्कि उत्पादन लागत के अनुपात में मुआवजे को बढ़ाया जाएगा। 30 अप्रैल तक प्रत्येक प्रभावित किसान और मजदूर के खाते में फसल नुकसान का मुआवजा जमा करवा दिया जाएगा।

23. कृषि व पशुपालन को लाभदायक बनाने के लिए एक विशेष योजना का शीघ्र

ही अनावरण किया जाएगा। बिजली, कार्डबोर्ड और कृषि आधारित उद्योगों के लिए पराली का उपयोग किया जाएगा, जो पंजाब के युवाओं को कृषि को लाभदायक बनाने के लिए रोजगार प्रदान करेगा। पंजाब की महिला किसानों की सुविधा के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। हमारी सरकार बीज उत्पादन को बढ़ावा देगी ताकि पंजाब बीज़ हब बन सके। फसल विविधीकरण और बासमती, कपास, सरसों, मक्का और तिलहन के तहत क्षेत्र को ध्यान में रखा जाएगा ताकि भूजल को भी बचाया जा सके।

24. भले ही पिछली सरकारें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) बांटने का दावा करती हैं, लेकिन जमीनी वास्तविकता इस से बिल्कुल अलग है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक किसान को उसके खेत का मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिले ताकि वह उसके अनुसार खाद आदि का उपयोग कर सके। इससे कृषि पर उनके खर्च में कमी आएगी और उनकी आय में इजाफा होगा। हमारी सरकार मौजूदा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करेगी और ब्लाक स्तर पर और प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी ताकि सभी किसान इन प्रयोगशालाओं का लाभ उठा सकें।

25. हमारी सरकार कृषि विभाग के ब्लाक कार्यालयों का जीर्णोद्धार करेगी ताकि सरकार की योजनाओं की जानकारी गांवों के हर घर में पहुंच सके और लोग उन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

26. हमारी सरकार पंजाब में पशु चिकित्सा सेवाओं, जानवरों की नस्लों के आनुवंशिक सुधार पर शोध, झींगा पालन और गुणवत्ता वाले मछली के बीज पर विशेष जोर देगी। डेयरी क्षेत्र के व्यावसायीकरण और मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्पाद मूल्यवर्धन, विपणन, ब्रांडिंग और बिक्री सहयोग

में सहयोग से सहिकारिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा।

27. पंजाब शहीदों और शूरवीरों की भूमि है जिन्हों ने मातृभूमि के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दीं। हमारी सरकार राज्य के देशभक्त और वीर जवानों को प्रणाम करती है जिन्होंने हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व किया। हमारी सरकार पंजाब के शहीद जवानों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की राहत/मानदेय देने के लिए प्रतिबद्ध है।

28. हमारी सरकार राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार राज्य के अनुसूचित जाति समुदाय के छात्रों को निरूशुल्क शिक्षा, कॉलेज के छात्रों के लिए मुफ्त विदेशी शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा सेवा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी।

29. पिछली सरकारों ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को हाशिए पर रखा है। इस के अलावा पटियाला, अमृतसर और फरीदकोट के सरकारी कॉलेजों की सीटों की संख्या में जिला स्तर पर मामूली सी वृद्धि हुई है। पंजाब के सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस की सिर्फ 675 सीटें हैं और पंजाब के आधा दर्जन निजी मेडिकल कॉलेजों में करीब 770 सीटें हैं जहां मेडिकल डिग्री के लिए छात्रों से न्यूनतम 50 लाख रुपये से लेकर 80 लाख रुपये फीस वसूली जाती है। गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र अच्छे रैंक के साथ भी इन सीटों को नहीं ले सकते हैं जबकि धनी परिवारों के छात्रों को ये सीटें औसत रैंक पर भी मिल जाती हैं। सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवारों से ताल्लुक रखने वाले ये छात्र यूक्रेन जैसे देशों में जाने को मजबूर हैं। हमारी सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए बड़े कदम उठाएगी ताकि पंजाब के

छात्र विदेश में पढ़ने के लिए विवश न हों।

30. पंजाब का भविष्य इसके युवाओं के साथ है और यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में एक विशिष्ट स्थान रखता है। राज्य के रचनात्मक उत्थान के लिए युवा शक्ति को शामिल करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। जालंधर भले ही खेल उद्योग का केंद्र है लेकिन यहां युवाओं को खेलों में प्रशिक्षण देने के लिए कोई संस्थान नहीं है। हमारी सरकार जालंधर में देश का सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय बनाएगी।

31. राज्य के युवाओं के लिए रोजगार की कमी राज्य में नशे की लत का प्रमुख कारण है और यह विदेशों में प्रवास का भी एक प्रमुख कारण है। ऐसा पिछली सरकारों की अक्षमता के कारण होता रहा है। भले ही कांग्रेस ने 2017 के पिछले चुनाव में पंजाब के हर घर में रोजगार देने का वादा किया था लेकिन पिछले पांच सालों में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। राज्य में नौकरियों की कमी ने इन बच्चों को अवसरों की तलाश में विदेश जाने को मजबूर कर दिया है।

32. हमारी सरकार पंजाब में रोजगार और व्यापार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवा कर इस रुझान को बदलने का यत्न करेगी। युवाओं को न केवल उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार और वेतन दिया जाएगा, बल्कि उन्हें स्टार्ट–अप के लिए नए अवसर भी प्रदान किए जाएंगे, ताकि वे भी रोजगार पैदा कर सकें।

33. हमारी सरकार राज्य के व्यापारियों और कारोबारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हम व्यापार और उद्योग के फलने–फूलने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेंगे। आने वाले पांच वर्षों में न तो कोई नया कर लगाया जाएगा और न ही कोई मौजूदा कर बढ़ाया जाएगा, ताकि राज्य से किसी भी व्यापार

अथवा कारोबार का पलायन न हो। हमारी सरकार पंजाब के विकास में व्यापारियों और उद्योगपतियों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। हमारी सरकार एक विशेष आयोग का गठन करेगी, जिसमें केवल व्यापारी और व्यवसायी सदस्य होंगे, जो निर्णय लेंगे और नीतियां बनाएंगे। हमारी सरकार नए उद्योगों, खासकर एमएसएमई को बढ़ावा देगी, जो पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ हैं। पंजाब के उद्योगों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए, हम अपने मौजूदा फोकल पुआंइटस में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की तत्काल बहाली की कोशिश करेंगे। औद्योगिक पुनःद्धार को बढ़ावा देने के लिए, विकसित औद्योगिक एस्टेट्स एवं फोकल पुआंइटस में अप्रयुक्त भूमि उद्योगों को प्रतिस्पर्धी दरों पर प्रदान की जाएगी।

34. यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि व्यवसायियों से हिस्सा मांगता है तो सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सरकार व्यापारियों के साथ मिलकर काम करेगी और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी। इंस्पेक्टर राज, छापामारी राज और नाजायज टैक्स को पूरी तरह खत्म कर के कारोबार के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जाएगा। व्यापारियों के खिलाफ पिछली सभी फर्जी एफआईआर को खत्म किया जाएगा। हमारी सरकार मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के साथ मिलकर काम करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पंजाब मैन्युफैक्चरिंग में विश्व स्तर पर खुद को मजबूती से स्थापित कर सके।

35. पंजाब राज्य एनआरआई के सबसे बड़े वर्ग वाले राज्यों में से एक है। किसी गांव, कस्बे या शहर में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा, जिसके एक या अधिक सदस्य विदेशों में न रहे हों। इन अप्रवासी भारतीयों का योगदान

वास्तव में बहुत बड़ा है लेकिन कभी–कभी इसे कम आंका जाता है। हमारी सरकार इस वर्ग को अपनी प्राथमिकताओं की सूची में उच्च स्थान पर रखने का प्रस्ताव रखती है। दोआबा क्षेत्र के अप्रवासी भारतीयों की लंबे समय से यह मांग रही है कि उनके क्षेत्र में उनके लिए एक हवाई अड्डा होना चाहिए। हमारी सरकार जालंधर में उनके लिए एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, सरकार एनआरआई के विभिन्न मुद्दों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करेगी।

36. बुनियादी सेवाएं लोगों का अधिकार हैं और उन्हें लालफीताशाही का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार राज्य में 'डोरस्टेप डिलीवरी सर्विसेज' प्रणाली को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि लोगों को बिचौलियों–दलालों और सरकारी कार्यालयों व सेवा केंद्रों में लंबी कतारों से राहत मिल सके। नागरिक अपने घरों के आराम से सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इस प्रणाली में आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं जैसे जाति एवं विवाह प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पानी / बिजली का नया कनेक्शन आदि की सेवाएं शामिल होंगी। इसके अलावा, हमारी सरकार एक जिला प्रदर्शन डैशबोर्ड विकसित करेगी जो जनता को सेवाएं प्रदान करने में हुई देरी के लिए जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा।

37. हमारी सरकार राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता में अडिग रहेगी और महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना तैयार करेगी जो पूरी दुनिया में महिला सशक्तिकरण के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना होगी और उनके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

38. हमारी सरकार, आरंभ में इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की

प्रत्येक महिला को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा जबकि वृद्ध महिलाओं को वरिष्ठ नागरिक पेंशन के साथ–साथ 1000 रुपये मिलेंगे। वित्तीय साक्षरता योजना के स्तंभों में से एक होगी। यह उन्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाएगी। यह उन्हें विकल्प देगी और वित्तीय समझ के साथ–साथ बचत, किफायत और निवेश को प्रोत्साहित करेगी।। यह उन्हें स्वतंत्र बनाएगी और उनकी छोटी–छोटी इच्छाओं को पूरा करने में उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी जैसे कि – हमारे समाज में बड़ी उम्र की महिलाएं अपनी बेटी के घर आने पर उसे कुछ देने में सक्षम होंगी, गृहिणियों को अपने बच्चों के लिए बार–बार अपने पति से मांगना नहीं पड़ेगा, बाजार से अपने लिए कुछ खरीदने के लिए लड़कियों को अपने पिता से पूछने की जरूरत नहीं होगी आदि।

39. पिछले कुछ वर्षों में राज्य को कानून और व्यवस्था के चरमराने और कानून के शासन के पतन के दोहरे खतरे से जूझते देखा गया है। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि शांति बनाए रखना और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा किसी भी सरकार का पहला नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। जबकि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में कानून लागू करने वाली एजेंसियां इस संबंध में निरंतर सतर्कता बनाए रखें, किसी भी स्थिति में उन्हें अन्यायपूर्ण और अंधाधुंध बल प्रयोग के माध्यम से आम नागरिक के अधिकारों और गरिमा को रौंदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कानून का राज अक्षरशः स्थापित होगा। यह दृष्टिकोण को वास्तविकता व सपनों से जोड़ने की दिशा में एक साहसिक प्रयास है।

40. हमारी सरकार पंजाब के लोगों को एक ईमानदार, सतर्क और सख्त सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि राज्य में कोई भी अपराध करने की हिम्मत न

करे और शांतिपूर्ण माहौल कायम रहे। राज्य में गैंगस्टरों द्वारा बरगाड़ी बेअदबी मामले सहित बम विस्फोट, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के सभी मामलों की गहनता से जांच की जाएगी ताकि उनके मास्टरमाइंड समेत सभी दोषियों पर कार्रवाई हो सके।

41. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस अधिकारियों की भर्ती भ्रष्टाचार मुक्त हो, तैनाती योग्यता और ईमानदारी के आधार पर हो और राज्य पुलिस के कामकाज में किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि या राजनीतिक नेता का हस्तक्षेप न हो। वीआईपी संस्कृति हमारी सरकार के लोकाचार के खिलाफ है और हमारी सरकार ने नियमों के खिलाफ किसी भी अतिरिक्त व्यक्तिगत सुरक्षा को वापस लेकर पुलिस बल के दुरुपयोग को रोकने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को मजबूत किया जाएगा। पुलिस बल की कार्य स्थितियों में भी सुधार होगा क्योंकि हमारी सरकार इस तथ्य से अवगत है कि पुलिस कठिन परिस्थितियों में काम करती है जिससे अक्सर तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। पुलिस बल की संवेदनशीलता को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

42. राज्य की सीमाओं की सुरक्षा सावधानी से की जाएगी ताकि कोई भी आतंकवादी राज्य में प्रवेश न कर सके और सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी न हो। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन सहित किसी भी सीमा पार खतरे को टालने व रोकने के लिए पुलिस बल नवीनतम और सर्वोत्तम तक़नीक से लैस हों।

43. हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और अपराध को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने के रास्ते में धन की कमी नहीं आने देगी। पूरे राज्य को सीसीटीवी नेटवर्क से कवर किया जाएगा जिस से राज्य में अपराध दर से निपटने में मदद मिलेगी।

44. हमारी सरकार छह महीने के अंदर राज्य को नशा मुक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन, निर्दोष लोगों के खिलाफ पिछली सभी फर्जी एफआईआर को खत्म कर दिया जाएगा और उन लोगों के मन से डर के भाव को समाप्त किया जाएगा।

45. कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं और सेवाओं के वितरण की एकमात्र प्रणाली होते हैं। पिछली सरकार ने इस महत्वपूर्ण वर्ग को शाही उपेक्षा का शिकार बनाया। हमारी सरकार इसे पूर्ववत करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि सरकार एक समृद्ध पंजाब के अपने सपने में प्रत्येक कर्मचारी को भागीदार मानती है।

46. हमारी सरकार आंगनबाडी और आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका वेतन और प्रोत्साहन राशि दोगुनी की जाएगी।

47. हमारी सरकार राज्य के वकीलों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उनके लिए कोर्ट परिसरों में चैंबर बनाए जाएंगे। हमारी सरकार उन्हें और उनके परिवारों को बीमा कवर प्रदान करेगी।

48. हमारी सरकार, राज्य में परिवहन माफिया को समाप्त करने और परिवहन क्षेत्र के सभी मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। परिवहन क्षेत्र के लिए 10 से 15 सदस्यों का एक आयोग गठित किया जाएगा जिसमें राज्य के परिवहन

संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आयोग द्वारा नई परिवहन नीति तैयार की जाएगी। इस आयोग के निर्णयों को सरकार द्वारा लागू किया जाएगा ताकि ट्रक संचालकों सहित इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को आने वाली समस्याओं का समय–समय पर समाधान किया जा सके।

49. लुधियाना, बठिंडा, अमृतसर और जालंधर सहित पंजाब के विभिन्न शहरों में साफ–सफाई का मुद्दा गंभीर है। शहरों में मौजूदा बाजारों में सड़कें जर्जर हैं और बाजारों में सार्वजनिक शौचालय या उचित पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। हमारी सरकार शहरों में उचित सीवेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सर्वोत्तम स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करेगी ताकि वे सुंदर दिखें। इसके अलावा, हमारी सरकार द्वारा पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय और बाजारों के लिए अन्य सुविधाओं सहित उचित बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा।

50. पंजाब गुरुओं और संतों की भूमि है और गुरबानी में भी पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। गुरु नानक देवजी ने अपने श्लोक 'पवण गुरु, पाणी पिता, माता धरत महत' के माध्यम से गुरु को वायु, पिता को जल और माता को पृथ्वी का दर्जा दिया है। मानव कल्याण का पर्यावरण से गहरा संबंध है। पिछले कुछ दशकों में, प्राकृतिक संसाधनों पर मानव द्वारा किए गए अतिक्रमण ने पर्यावरण पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव डाला है। हमारी सरकार पर्यावरण में सुधार के लिए नए कदम उठाएगी।

51. हमारी सरकार, राज्य की नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान देगी। इसे हासिल करने के लिए, सभी शहरों और कस्बों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों और सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

52. हमारी सरकार गाँव के तालाबों की सफाई और सुधार पर भी विशेष बल देगी जिससे भूजल पुनर्भरण के माध्यम से जल स्तर में सुधार करने में भी मदद मिलेगी।

53. हमारी सरकार द्वारा पंजाब के नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। कोयला, फर्नेस ऑयल आदि प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस और अन्य स्वच्छ ईंधन अपनाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा और इसके लिए नीति स्तर पर आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

54. खेतों में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए, हमारी सरकार बिजली उत्पादन और औद्योगिक ईंधन आदि के रूप में पराली के उपयोग जैसे प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को प्रदर्शित और बढ़ावा देगी।

55. परिवहन क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए नए तकनीकी हस्तक्षेप जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी संचालित वाहन आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा। वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा।

56. हमारी सरकार ने ऐसे समय में कार्यभार संभाला है जब राज्य एक गंभीर आर्थिक संकट की चपेट में है और इस में पिछली सरकार द्वारा लिए गए ऋण राज्य के कुल योजना व्यय को पार कर गए हैं। बेरोजगारी की भयावहता खतरनाक अनुपात तक पहुंच गई है और बढ़ती ही जा रही है। महंगाई ने आम आदमी, खासकर गरीबों की कमर तोड़ दी है। यह आर्थिक संकट पक्षपातपूर्ण प्राथमिकताओं के साथ–साथ उपेक्षा का भी परिणाम है। राजकोषीय प्रबंधन के

प्रति पिछली सरकारों के दृष्टिकोण में गंभीर विकृतियां रही हैं, जिससे राज्य पतन की ओर जा रहा है। इन चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में संबोधित किया जाना है, और हमारी सरकार इस पर तुरंत प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव रखती है।

57. पिछले कुछ वर्षों से राज्य की वित्तीय स्थिति मुख्य रूप से आय और व्यय के बीच बेमेल होने के कारण गंभीर बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में बड़े राजकोषीय घाटे के बने रहने से चौंका देने वाला ऋण खड़ा हो गया है जो अब 3.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार राज्य को ऋणग्रस्त राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य वित्तीय रिपोर्ट 2021–22 के अनुसार, पंजाब का ऋण – सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात 42.5% है – जो जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बाद सबसे अधिक है। यह स्पष्ट रूप से पंजाब को भारत में सबसे अधिक ऋणी बड़े राज्य के रूप में दिखाता है।

58. बढ़ते कर्ज का बोझ बहुत चिंता का विषय है और हमारी सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हमारी सरकार आम लोगों, व्यापारियों, कारोबारियों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों से उन को पेश आ रही समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान खोजने के लिए सुझाव लेगी और उनके सुझावों को ध्यान में रखते हुए राज्य का बजट तैयार किया जाएगा। बजट और सरकारी योजनाओं में राज्य के उपेक्षित और वंचित वर्गों की राय प्रतिबिंबित होगी।

59. अंत में, मैं राज्य को शांति, विकास और समृद्धि के पथ पर आगे ले जाने के

हमारी सरकार के संकल्प को दोहराना चाहूंगा। इस के लिए यह सभी के सहयोग और मदद की अपेक्षा करती है, भले ही वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो। इस के लिए, हमारी सरकार विशेष रूप से विपक्षी दल की तरफ मित्रता और सहयोग का हाथ बढ़ाती है। यह प्रतिबद्ध है कि अतीत की कड़वाहट को अतीत में ही दफना दिया जाए। यह शांति, समृद्धि और सर्वांगीण विकास के वायदे के लक्ष्य की समयबद्ध पूर्ति हेतु अग्रसर होने के लिए संकल्पित है। हमारी सरकार पूरे समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ, पंजाब की क्षमता में विश्वास करते हुए और अपने नागरिकों के सहयोग से, पंजाब को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम करेगी क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाब देश का अव्वल राज्य बन सकता है।

60. मैं आप सभी के सुखद और सार्थक कार्यकाल की कामना करता हूं और मुझे विश्वास है कि सदन में चर्चा सभी राजनीतिक बाधाओं को दरकिनार रख कर की जाएंगी और लोकतांत्रिक मूल्यों, गरिमा की उच्चतम परंपराओं को प्रतिबिंबित करेंगी और राज्य की प्रगति और कल्याण के लिए हमारी चिंताओं को अल्पकालिक राजनीतिक लाभ से ऊपर रखेंगी।

जय हिन्द !

10770/03-2022/400/Punjab Govt. Press, S.A.S. Nagar